the Speaker may direct four members from among themselves to serve as members of the National Shipping Board to be reconstituted with effect from the 8th June, 1967."

The motion was adopted.

(ii) NATIONAL FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION LIAISON COMMITTEE

Shri Annasahib Shinde: I beg to move:

"That in pursuance of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation Resolution No. F-10-1|65 FAIT, dated the 9th September, 1966, as subsequently amended, the members of Lok Sabha do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct, four members from among themselves to serve as members of the National Food and Agriculture Organisation Liaison Committee for a term of three years, subject to the other provisions of the said Resolution."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That in pursuance of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation Resolution No. F-10-1|65 FAIT dated the 9th September, 1966, as subsequently amended, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, four members from among themselves to serve as members of the National Food and Agriculture Organisation Liaison Committee for a term of three years, subject to the other provisions of the said Resolution."

The motion was adopted.

14.4 hrs.

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION—contd.

Mr. Deputy-Speaker: The House will now resume general discussion of the Railway Budget. Shri Vajpayee.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह घाटे का बजट है, और पच्चीस सालों में पहली बार यह घाटे का बजट रक्खा गया है। यह घाटे का बजट रेलों में दिखाई जाने वाली उस लाल झंडी की तरह से है जिसे न देखने का अर्थ होगा रेलों को एक वित्तीय खाई में पटकना और देश के अर्थ संकट को और भी गहरा करना।

रेलवे मंत्री ने यह कहा है कि घाटे का कारण कम माल की ढुलाई का होना है। माल ढोने का जो अनुमान लगाया गया था उस की तुलना में प्रायः 80 लाख टन कम माल ढोया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यह अनुमान लगाने के लिये जिम्मेदार कौन है? रेलों को कितना माल ढोना पड़ेगा इस का गलत अनुमान लगाया गया, और इस गलती के लिये योजना आयोग और अन्य मंत्रालय उत्तरदायी हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनकी गलती के लिये अब यात्रियों पर किराया बढ़ाया जा रहा है और माल ढोने की दर में भी वृद्धि की जा रही है।

रेलवे मंत्रालय स्वयम् किस तरह से अनुमान लगाता है यह हम ने मार्च और मई में पेश किये गये बजट में देखा। मार्च के बजट में अनुमान था कि कुल मिला कर 15 करोड़ रु० का घाटा होगा, लेकिन मई के बजट में घाटा 15 करोड़ रु० से बढ़ कर 24 करोड़ रु० हो गया। अब यदि रेलवे मंत्रालय दो महीनों की अवधि में अपने अनुमानों में इतना अन्तर करता है तो समझना चाहिये कि न तो आमदनी के अनुमान सही किये जाते हैं और न खर्च के अनुमान सही किये जाते हैं और न माल ढोने के बारे में जो लक्ष्य निर्धारित किये